(b) The revision of indigenous newsprint price is not likely to have any significant impact on the public or on the growth of the Dress in general.

(c) and (d) An assurance was given in January, 1985, on the floor of Rajya Sabha that the newsprint users would get an opportunity to go before the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) and make their representations when the next review of indigenous newsprint price was taken up. Accordingly, an opportunity was given by the BICP to the representatives of Newspaper Associations before finalising their recommendations on indigenous newsprint prices in 1985.

गैस एजेंसी के विरुद्ध शिकायत

525 **श्री निर्जा इर्शादबेग** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के साबरकांठा जिले का मोडासा नगर किस गैस एजेंसी से सम्बद्ध है तथा उसके पास गैस कनैक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन है और इस प्रतीक्षा सूची के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है तथा मोडासा में हाल ही में कितने गैस कनैक्शन मंजूर किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को इस गैस एजेंसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार और जानबूझकर गैस सिलेंडरों की सप्लाई में विलम्ब करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस गैस एजेंसी के विरुद्ध लगाये गये गलतियों तथा भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने का विचार रखती है और यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) मैसर्स दामोर गैस एजेंसी मोड़ासा के पास 1300 उपभोक्ताओं के नाम की सूची थी जिनमें से गत कुछ महीनों में 100 नए कनेक्शन दिये गये हैं । वर्ष 1989 के आरम्भ में 2000 नामों की प्रतीक्षा सूची के पूरे हो जाने की सम्भावना है रिफिल सप्लाई के सम्बन्ध में इस डीलर के विरुद्ध की शिकायतें तेल कम्पनी को प्राप्त हुई हैं । वितरण अनुशासन निर्देशों के अनुसार इस वितरण शिप के क्रियाकलापों पर तेल कम्पनी द्वारा सूक्ष्म नजर रखी जा रही है और इसमें सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

आधुनिक तकनीकों के संबंध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग

526 **श्री मिर्जा इर्शादबेग** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन बड़े देशों से आधुनिक तकनीकों के सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग की गई है ;

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये लाइसेंस देने के लिये सहमत हो गया है, यदि हां, तो कब तथा कितनी मात्रा में ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1987 के दौरान सरकार ने विदेशी सहयोग के 853 प्रस्ताव स्वीकृत किये थे । यू० के०, यू० एस० ए०, पश्चिम जर्मनी तथा जापान प्रमुख देश हैं । 1987 में स्वीकृत कुल विदेशी सहयोग प्रस्तावों में इनका हिस्सा 63% (लगभग) है ।

(ख) और (ग) 1987 में स्वीकृत कुल 853 विदेशी सहयोग प्रस्तावों में से, 196 विदेशी सहयोग अमरीकी फर्मों के साथ किये गये । इन स्वीकृत विदेशी सहयोगों के ब्यौरे अर्थात् भारतीय तथा विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु तथा सहयोग की किस्म भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके मासिक न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं । इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।